International Journal of Research inSocial Science
Vol. 11 Issue 12, December 2021,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

नई शक्षा नीति, 2020 पर एक अध्ययन और उच्च शक्षा पर इसका प्रभाव

सुधीर कुमार संह
सहायक प्रोफेसर बीएड
महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महा वद्यालय हरदोई

सार:

भारत की स्वतंत्रता के 73वें वर्ष के पूरा होने का प्रतीक है, फर भी राष्ट्र में 100% साक्षरता या सार्वभौ मक साक्षरता का लक्ष्य है। स्वतंत्र भारत के लए जो दृष्टिकोण और लक्ष्य निर्धारित कए गए थे, उन पर चंतन करना आवश्यक है। दृष्टि राष्ट्र में समानता और शक्षा में समानता देखने की है। यह भारत में शक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता को दर्शाता है। इसके आलोक में महामारी वर्ष के बीच प्रख्यात वैज्ञानिक डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में नई राष्ट्रीय शक्षा नीति लागू हुई है। राष्ट्रीय शक्षा नीति सभी को उच्च गुणवत्ता वाली शक्षा प्रदान करके हमारे राष्ट्र को एक समान और जीवंत ज्ञान समाज में स्थायी परिवर्तन में सीधे योगदान देती है। नई राष्ट्रीय शक्षा नीति को 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित कया गया था जो ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में प्रारं भक शक्षा से लेकर उच्च शक्षा के साथ-साथ व्यावसायिक प्र शक्षण के लए एक व्यापक ढांचा है। नई नीति का उद्देश्य 2030 तक स्कूली शक्षा में 100 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) के साथ पूर्व- वद्यालय से माध्य मक स्तर तक शक्षा का सार्वभौ मकरण करना है और 2025 तक उच्च शक्षा में जीईआर को 50 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य है। कई अवसर हैं और एनईपी 2020 के कार्यान्वयन में शक्षा बिरादरी के लए चुनौतियां। यह पेपर उच्च शक्षा पर राष्ट्रीय शक्षा नीति का प्रभाव: अवसर और चुनौतियां, भारत में शक्षा प्रणाली के इतिहास का पता लगाने की को शश करता है, एचई के संबंध में एनईपी की समीक्षा करने के लए, प्रभाव का वश्लेषण करने के लए। शक्षकों पर एनईपी का, और एनईपी के कार्यान्वयन में अवसरों और चुनौतियों को भी व्यक्त करता है और एनईपी के आगे की राह का भी वर्णन करता है। कीवर्ड: राष्ट्रीय शक्षा नीति, उच्च शक्षा, सार्वभौ मकरण, शक्षकों पर प्रभाव

परिचय:

राष्ट्रीय शक्षा नीति भारतीय शक्षा प्रणाली के सामने आने वाले गंभीर मुद्दों के समाधान के लए एक नई नीति है। NEP 2020 जिसे 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित कया गया था, भारत की नई शक्षा प्रणाली के दृष्टिकोण को रेखां कत करता है। राष्ट्रीय शक्षा नीति 2020 एक भारत केंद्रित शक्षा प्रणाली की कल्पना करती है जो सभी को उच्च गुणवत्ता वाली शक्षा प्रदान करके हमारे देश को एक समान और जीवंत ज्ञान समाज में बदलने में सीधे योगदान देती है।

यह एनईपी शक्षा की पछली राष्ट्रीय नीति 1986 की जगह लेता है। नई नीति पूर्व भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) डॉ के कस्तूरीरंगन के नेतृत्व वाली एक स मति द्वारा तैयार कए गए मसौदे पर आधारित है। स मति पछले छह वर्षों से नीति पर काम कर रही है और कस्तूरीरंगन स मति नीति पर काम करने वाली दूसरी स मति है। एनईपी भारत की शक्षा नीति में कई बदलाव करता है।

एनईपी 2020 ने उच्च शक्षा संस्थानों (एचईआई) की गुणवत्ता में सुधार और भारत को वैश्विक शक्षा केंद्र के रूप में स्था पत करते हुए उच्च शक्षा में जीईआर को 26.3 प्रतिशत (2018) से 2035 तक लगभग दोगुना करने के महत्वाकांक्षी कार्य की रूपरेखा तैयार की है। एक अंतः वषय दृष्टिकोण के माध्यम से एक लचीला पाठ्यक्रम प्रदान करने, चार साल के स्नातक कार्यक्रम में कई निकास बिंदु बनाने, अनुसंधान को उत्प्रेरित करने, संकाय समर्थन में सुधार और अंतर्राष्ट्रीयकरण को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित कया गया है।

पूरे उच्च शक्षा खंड के लए भारतीय उच्च शक्षा आयोग (एचईसीआई) की स्थापना में सबसे आमूलचूल बदलाव देखा जाएगा। एचईसीआई एक एकल नियामक के रूप में कार्य करेगा और मान्यता, वत्त पोषण और शैक्ष णक मानक सेटिंग सहित कई कार्य स्वतंत्र वर्टिकल द्वारा कए जाएंगे। ये संस्थाएं अंततः वश्व वद्यालय जैसे अन्य नियामक निकायों की जगह लेंगी अनुदान आयोग (यूजीसी) या अ खल भारतीय तकनीकी शक्षा परिषद (एआईसीटीई)।

भारत के प्रधानमंत्री श्री. नरेंद्र मोदी ने कहा क नीति "क्या सोचना है इसके बजाय कैसे सोचना है" पर केंद्रित है।

अध्ययन का उद्देश्य:

<u>अध्ययन नीचे उल्लि खत उद्देश्यों को पूरा करने के लए कया जाता है:</u>

1 उच्च शक्षा के संबंध में एनईपी की मुख्य वशेषताएं जानने के लए

2 भारतीय शक्षा प्रणाली के इतिहास और इसकी वर्तमान स्थिति का पता लगाने के लए।

3 उच्च शक्षा पर राष्ट्रीय शक्षा नीति 2020 के प्रभाव का वश्लेषण करना।

<u>कार्यप्रणाली:</u>

कार्यप्रणाली में उच्च शक्षा प्रणाली के संबंध में एनईपी 2020 की नीति के व भन्न वर्गों पर प्रकाश डालते हुए, राष्ट्रीय शै क्षक नीति ढांचे के सार को उजागर करने पर एक वैचारिक चर्चा शा मल है। उच्च शक्षा पर एनईपी का प्रभाव फोकस समूह चर्चा पद्धति का उपयोग करके बनाया गया है। उच्च शक्षा से संबं धत नई नीति की चुनौतियों और अवसरों का वश्लेषण भ वष्य कहनेवाला वश्लेषण तकनीक का उपयोग करके कया जाता है।

भारत की शक्षा नीति का वकास: स्वतंत्रता से आज तक का एक रोड मैप:

भारत की स्वतंत्रता के बाद पहली स मति वश्व वद्यालय शक्षा आयोग 1948-49 थी जिसे राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इस स मति का नेतृत्व सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कया था जो उच्च शक्षा पर केंद्रित था।

माध्य मक शक्षा आयोग 1952-53 ने प्राथ मक वद्यालय के बाद और वश्व वद्यालय शक्षा शुरू होने से पहले मुख्य रूप से शक्षा पर ध्यान केंद्रित कया।

शक्षा आयोग 1964-66 को डॉ. डी. एस कोठारी के नेतृत्व में कोठारी आयोग के रूप में भी जाना जाता है। इस आयोग का एक समग्र दृष्टिकोण था और प्राथ मक से स्नातकोत्तर तक प्रत्येक चरण को ध्यान में रखते हुए शक्षा के राष्ट्रीय पैटर्न और सामान्य नीतियों पर सरकार को सलाह देता था।

1968 में, कोठारी आयोग की सफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा शक्षा पर राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गई थी और राष्ट्रीय एकीकरण और अ धक आ थक और सांस्कृतिक वकास को प्राप्त करने के लए समान शै क्षक अवसरों की नीति की घोषणा की गई थी।

शक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 ने शक्षा प्रणाली में असमानताओं को दूर करने पर वशेष जोर दिया और सभी के लए शै क्षक अवसर को समान करने का लक्ष्य रखा। इस अ धनियम को 1992 में संशो धत कया गया था "सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम" वशेष रूप से महिलाओं, अनुसू चत जनजातियों (एसटी) और अनुसू चत जाति (एससी) के लए।

2009 में, बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शक्षा का अ धकार (RTE) अ धनियम पारित कया गया, जिसने प्रारं भक शक्षा को प्रत्येक बच्चे के लए एक मौ लक अ धकार बना दिया।

टी.एस.आर. 2016 में नई शक्षा नीति के वकास के लए सुब्रमण्यम स मति या स मति ने कार्यान्वयन अंतराल को दूर करके शक्षा की गुणवत्ता और वश्वसनीयता में सुधार करने की मांग की।

अंत में डॉ. के. कस्तूरीरंगन स मति को नई राष्ट्रीय शक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लए तैयार कया गया और 31 मई, 2019 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस मसौदे में वर्तमान शक्षा प्रणाली के सामने पहुंच, इक्विटी, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही की चुनौतियों का समाधान करने की मांग की गई थी। स मति ने मानव संसाधन वकास मंत्रालय को शक्षा मंत्रालय में बदल दिया।

<u>उच्च शक्षा प्रणाली के लए नीतियां एनईपी 2020 की मुख्य वशेषताएं:</u>

<u>नीति में बदलाव:</u>

1. व्यावसायिक शक्षा सहित एचई में सकल नामांकन अनुपात वर्तमान 26.3% (2018) से बढ़कर 2035 तक 50% हो जाएगा।
2. उच्च गुणवत्ता प्रदान करने वाले उच्च शक्षा संस्थानों को सरकार से अ धक प्रोत्साहन मलेगा।
3. प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय वश्व वद्यालयों को भारत में कैंपस स्था पत करने के लए प्रोत्साहित कया जाएगा।
4. उच्च शक्षा संस्थान बहु वषयक शक्षा और लचीली पाठ्यचर्या संरचना को बढ़ावा देंगे जो आजीवन सीखने के लए नई संभावनाएं पैदा करने के लए कई प्रवेश और निकास बिंदु प्रदान करेगी।

5. ऑनलाइन शक्षा और ओपन डस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) पर अ धक ध्यान केंद्रित करना, एक्सेस इक्विटी और समावेशन में सुधार के प्रमुख साधन के रूप में

6. उच्च शक्षा के भीतर व्यावसायिक शक्षा का एकीकरण। 2025 तक कम से कम 50% शक्षा र्थयों को व्यावसायिक शक्षा का अनुभव होगा।

7. अ धक अंतरराष्ट्रीय छात्रों को आक र्षत करने के लए HE गुणवत्ता को वैश्विक गुणवत्ता स्तर तक सुधारा जाएगा और पुरस्कार के लए वदेशों में अर्जित क्रे डट की गणना की जाएगी।

स्वास्थ्य शक्षा प्रणाली को इस तरह से एकीकृत कया जाना चाहिए क एलोपै थक च कत्सा शक्षा के सभी छात्रों को आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक च कत्सा, यूनानी, सद्ध और होम्योपैथी (आयुष) और इसके वपरीत की बुनियादी समझ होनी चाहिए। नवारक स्वास्थ्य देखभाल और सामुदायिक च कत्सा के लए स्वास्थ्य देखभाल शक्षा के सभी रूपों में अ धक जोर दिया जाना चाहिए।

तकनीकी शक्षा बहु- वषयक शक्षा संस्थानों के भीतर प्रदान की जानी चाहिए और अन्य वषयों के साथ गहराई से जुड़ने के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके अलावा आर्टि फ शयल इंटे लजेंस (एआई), 3-डी मशीनिंग, बिग डेटा एना ल सस और मशीन लर्निंग की पेशकश पर फोकस होना चाहिए स्वास्थ्य, पर्यावरण और टिकाऊ जीवन के लए अनुप्रयोगों के साथ जीनो मक अध्ययन, जैव प्रौद्यो गकी, नैनो प्रौद्यो गकी, तंत्रिका वज्ञान।

<u>शासी नकाय:</u>

• यूजीसी, एआईसीटीई, एमसीआई, डीसीआई, आईएनसी आदि जैसे एचई मॉनिटरिंग और कंट्रो लंग संस्थानों को एचईआई के लए एकल नियामक के रूप में भारतीय उच्च शक्षा आयोग (एचईसीआई) के साथ मला दिया जाएगा।

• नैक और एनएबी जैसे मौजूदा प्रत्यायन संस्थानों को एक मजबूत राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (एनएसी) द्वारा प्रतिस्था पत कया जाएगा।

• एक अकाद मक बैंक ऑफ क्रे डट (एबीसी) की स्थापना की जाएगी जो व भन्न मान्यता प्राप्त एचईआई (स्वयं और ओडीएल मोड) से अर्जित सभी पंजीकृत उम्मीदवारों के अकाद मक क्रे डट को डजिटल रूप से संग्रहीत करेगा, जिसे कॉलेज या वश्व वद्यालय द्वारा डग्री प्रदान करते समय ध्यान में रखा जा सकता है।

• वर्तमान में उपयोग कए जाने वाले व भन्न नामकरण जैसे मानद वश्व वद्यालय, संबद्ध वश्व वद्यालय, केंद्रीय वश्व वद्यालय, संबद्ध तकनीकी वश्व वद्यालय, एकात्मक वश्व वद्यालय, आदि को मानदंडों के अनुसार आवश्यक मानदंडों को पूरा करने के बाद ' वश्व वद्यालय' द्वारा प्रतिस्था पत कया जाएगा।

नेशनल स्कॉलर शप पोर्टल को मजबूत कया जाएगा और वश्व वद्यालयों तक वस्तारित कया जाएगा ता क योग्यता-आधारित छात्रों की वत्तीय जरूरतों को पूरा कया जा सके। नजी एचईआई को अपने छात्रों को बड़ी संख्या में मुफ्त जहाजों और छात्रवृत्तियों की पेशकश करने के लए प्रोत्साहित कया जाएगा

वश्व वद्यालय स्तर:

1. मौजूदा खं डत एचईआई का दो प्रकार के बहु- वषयक वश्व वद्यालयों (एमयू) और बहु- वषयक स्वायत्त कॉलेजों (एसी) में समेकन।

2. बहु वषयक वश्व वद्यालय दो प्रकार के होंगे जैसे (1) अनुसंधान-गहन वश्व वद्यालय, और (2) शक्षण-प्रधान वश्व वद्यालय।

3. वश्व वद्यालयों और कॉलेजों में अनुसंधान के वत्तपोषण के लए एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ) की स्थापना।

4. अनुसंधान को यूजी, पीजी, स्तर में शा मल कया जाएगा और इसमें समग्र और बहु- वषयक शक्षा दृष्टिकोण होगा।

5. सभी एचईआई (1) स्टार्ट-अप इन्क्यूबेशन केंद्र, (2) प्रौद्यो गकी वकास केंद्र, (3) अनुसंधान के सीमांत क्षेत्रों में केंद्र, (4) उद्योग-शैक्ष णक जुड़ाव केंद्र, और (5) मान वकी और सामाजिक वज्ञान अनुसंधान सहित अंतः वषय अनुसंधान केंद्र।

6. सभी उच्च शक्षा संस्थानों में पेशेवर शैक्ष णक और करियर परामर्श केंद्र होंगे, जिसमें सभी छात्रों के लए परामर्शदाता उपलब्ध होंगे ता क शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक कल्याण सुनिश्चित कया जा सके।

7. सभी एचईआई वज्ञान, ग णत, क वता, भाषा, साहित्य, वाद- ववाद, संगीत के क्षेत्र में आवश्यकतानुसार संकाय और अन्य वशेषज्ञों की सहायता से छात्रों द्वारा आयोजित वषय-केंद्रित क्लबों और गति व धयों के लए वकास, समर्थन और नि ध प्रदान करेंगे। खेलकूद, आदि

8. गुणवत्ता के वैश्विक मानक को प्राप्त करने के लए डग्री कार्यक्रमों में 40:30:30 अनुपात मॉडल के साथ इन-क्लास शक्षण, ऑनलाइन शक्षण घटक और ओडीएल घटक शा मल हो सकते हैं।

9. सभी निजी वश्व वद्यालय अपनी प्रत्यायन स्थिति के आधार पर श्रेणीबद्ध स्वायत्तता के पात्र हैं।

1. सभी निजी वश्व वद्यालयों/स्वायत्त कॉलेजों को अपने वत्तीय लेनदेन में खुलापन बनाए रखना होगा और लेखा प्रणाली में कसी भी तरह की अनिय मतता के लए बीओजी जिम्मेदार है। बीओजी में एचईआई के तेजी से वकास का मार्गदर्शन करने के लए अपने पेशेवर क्षेत्र में प्रतिष्ठित लोगों को शा मल करना चाहिए।

2. कानून की शक्षा प्रदान करने वाले वश्व वद्यालयों/संस्थानों को भ वष्य के वकीलों और न्यायाधीशों के लए अंग्रेजी और राज्य भाषा में द् वभाषी शक्षा प्रदान करना पसंद करना चाहिए।

चतुर्थ संस्थान स्तर:

1. बहु अनुशासनिक स्वायत्त महा वद्यालय परिसर में 3,000 से अ धक छात्र होंगे। बहु- वषयक बनने की समय सीमा 2030 तक है और 2040 तक 3,000 और अ धक छात्र हैं।

2. प्रत्येक मौजूदा कॉलेज या तो डग्री देने वाले स्वायत्त कॉलेज के रूप में वक सत होगा या वश्व वद्यालय के एक सं वधान कॉलेज में स्थानांतरित हो जाएगा और पूरी तरह से वश्व वद्यालय का हिस्सा बन जाएगा।

3. सभी मौजूदा संबद्ध कॉलेज अंततः निर्धारित मान्यता स्तर में सुधार और सुर क्षत करके संबद्ध वश्व वद्यालय के परामर्श समर्थन के साथ स्वायत्त डग्री देने वाले कॉलेज वक सत करेंगे।
4. कई निकास वकल्पों के साथ चार साल की बैचलर डग्री, एक से दो साल की मास्टर डग्री, बैचलर डग्री में बिताए गए वर्षों की संख्या के आधार पर क्रमशः चार या तीन, और पीएचडी करने का वकल्प। चार साल के लए शोध के साथ स्नातक की डग्री संभव है।
5. द् वतीय वर्ष में पूर्ण शोध के साथ दो वर्ष की मास्टर डग्री, चार वर्षीय स्नातक डग्री धारकों के लए एक वर्ष की मास्टर डग्री और पांच वर्ष की एकीकृत स्नातक/मास्टर डग्री।
6. उच्च शक्षा संस्थानों को सामान्य शक्षा के साथ एकीकृत कार्यक्रमों के माध्यम से कृ ष और पशु च कत्सा वज्ञान में पेशेवरों को तैयार करने के लए प्रोत्साहित कया जाएगा। कृ ष शक्षा की पेशकश करने वाले उच्च शक्षा संस्थानों को स्थानीय समुदाय पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और प्रौद्यो गकी ऊष्मायन और प्रसार को बढ़ावा देने के लए क्षेत्र में कृ ष प्रौद्यो गकी पार्क स्था पत करने में शा मल होना चाहिए।
7. सभी उच्च शक्षा संस्थानों को अपनी फीस संरचना तय करने में स्वायत्तता है और यदि कोई अ धशेष है तो उसे पारदर्शी लेखा प्रणाली के साथ वस्तार परियोजनाओं में पुनर्निवेश कया जाना चाहिए।
8. सभी निजी उच्च शक्षा संस्थानों को मेधावी छात्रों के लए पाठ्यक्रम शुल्क में 20% फ्री- शप और 30% छात्रवृत्ति प्रदान करनी चाहिए, जो वे कसी दिए गए शैक्ष णक वर्ष के दौरान प्रदान करते हैं और इसे मान्यता प्र क्रया द्वारा जांचा और पुष्टि की जानी चाहिए।

<u>छात्र स्तर</u>

1. शक्षक केंद्रित शक्षण मॉडल के बजाय छात्र केंद्रित शक्षण और सीखने की प्र क्रया।
2. च्वाइस बेस्ड क्रे डट सस्टम को एक नवोन्मेषी और लचीली सक्षमता आधारित क्रे डट सस्टम द्वारा संशो धत कया गया है।
3. परीक्षा प्रणाली हाई-स्टेक परीक्षाओं (सेमेस्टर एंड सस्टम) से एक अ धक सतत और व्यापक मूल्यांकन परीक्षा प्रणाली की ओर बदल जाएगी।
4. उच्च शक्षा संस्थानों में शक्षाशास्त्र संचार, प्रस्तुति, चर्चा, वाद- ववाद, अनुसंधान, वश्लेषण और अंतः वषय सोच पर केंद्रित होगा।

<u>नई राष्ट्रीय शक्षा नीति के प्रभाव का अध्ययन निम्न ल खत शीर्षकों के तहत कया जा सकता है: बड़े पैमाने पर समेकन से गुणवत्तापूर्ण वश्व वद्यालयों और कॉलेजों में मदद मलेगी</u>:

संस्थागत पुनर्गठन और समेकन का देश में उच्च शक्षा संस्थानों के मूल्य की मात्रा को लगभग एक तिहाई तक कम करके महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। हालां क यह ध्यान देने योग्य है क भारत में प्रति कॉलेज औसत नामांकन वर्तमान में 693 (एआईएसएचई 18-19, मानव संसाधन वकास मंत्रालय, केपीएमजी इन इं डया एना ल सस) है, जब क नीति का उद्देश्य 3000 से अ धक नामांकन के साथ उच्च शक्षा संस्थान बनाना है। यह नई नीति उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लए अ धक संख्या में स्वायत्त कॉलेजों पर केंद्रित है। भारत में 1000 से कम स्वायत्त कॉलेज भारत में लगभग 40,000

कॉलेजों में से हमारे मौजूदा हैं। इससे पता चलता है क भारत के उच्च शक्षा संस्थानों में नीति की सीमा में बहुत सारे समेकन और सहयोग होंगे। यह उम्मीद की जाती है क उपरोक्त कदम के परिणामस्वरूप उच्च शक्षा संस्थान भारत के 50000 कॉलेजों से 15000 कॉलेजों में आ जाएंगे।

बहु- वषयक शक्षा पर ध्यान दें:

भारतीय उच्च शक्षा प्रणाली को IIT IIM और AIIM जैसे उत्कृष्टता के एकल अनुशासनात्मक द्वीपों की वशेषता है। नई राष्ट्रीय शक्षा नीति संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड कंगडम में बड़े बहु- वषयक वश्व वद्यालयों के निर्माण की ओर बढ़ रही है, जिन्हें बहु- वषयक शक्षा और अनुसंधान वश्व वद्यालय (एमईआरयू) कहा जाता है। MERU का निर्माण देश के सभी जिलों और दूरदराज के स्थानों को कवर करते हुए, समाज के सभी क्षेत्रों में व वध क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शक्षा तक पहुंच प्रदान करेगा। इससे छात्रों को अपनी रु च के क्षेत्रों के चयन में व्यापक गुंजाइश मलेगी।

फैकल्टी की कमी और फैकल्टी क्वा लटी में सुधार की जरूरत:

शक्षा का अ धकार अ धनियम 1:30 के बाद वर्तमान संकाय छात्र अनुपात हमारा देश है, इसे 1:20 तक सुधारना चाहिए जिसे स्वस्थ अनुपात माना जाता है। इस संशोधन से सस्टम में न्यूनतम 500000 नए संकाय सदस्यों की भर्ती होगी। फैकल्टी की कमी को दूर करने के अलावा फैकल्टी की गुणवत्ता पर भी ध्यान देने की जरूरत है। 2022 तक शक्षकों के लए राष्ट्रीय पेशेवर मानक (एनपीएसटी) का एक सेट बनाया जाएगा जो कार्यकाल, निरंतर व्यावसायिक वकास प्रयासों, वेतन, पदोन्नति और अन्य मान्यता सहित शक्षक कैरियर प्रबंधन के सभी पहलुओं को निर्धारित करेगा। नीति शक्षकों के लए प्रदर्शन मानकों को बनाने के बारे में भी बात करती है जिसमें स्पष्ट रूप से उस चरण के लए आवश्यक वशेषज्ञता और दक्षताओं के व भन्न स्तरों पर शक्षक की भू मका का वर्णन कया गया है।

अनुसंधान गति व धयों को उत्प्रेरित करना:

एनईपी द्वारा प्रस्ता वत नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एनआरएफ) गुणवत्ता अनुसंधान की ओर एक सम र्पत ध्यान केंद्रित करने की संभावना है, जिसमें अनुसंधान फं डंग को प्रतिस्पर्धी बनाकर और वत्त पोषण प्र क्रयाओं की दक्षता में सुधार करके अनुसंधान पहलों के वत्तपोषण के लए अ धक ल क्षत दृष्टिकोण शा मल है। छात्रों में उनकी छोटी उम्र से ही अनुसंधान गति व धयों को आत्मसात कया जाएगा।

ओपन डस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) और ऑनलाइन कार्यक्रमों के माध्यम से पहुंच और इक्विटी में सुधार: भारत में कुल उच्च शक्षा नामांकन के लगभग 40 लाख यानी 11% शक्षार्थी ओडीएल के माध्यम से हैं। महामारी के मुद्दे से ओडीएल प्रणाली में भी सुधार होता है, और आने वाले वर्षों में इसमें उल्लेखनीय वृ द्ध देखने को मल सकती है जो भारत के सकल नामांकन को दोगुना करने में मदद करेगी।

निष्कर्ष:

नई राष्ट्रीय शक्षा नीति 2020 एक अच्छी नीति है क्यों क इसका उद्देश्य शक्षा प्रणाली को 21वीं सदी की जरूरतों और 2030 के सतत वकास लक्ष्यों के अनुरूप समग्र लचीला बहु- वषयक बनाना है। एनईपी एक व्यापक अभ्यास का एक उत्पाद है जो 2030 तक 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने का प्रयास करता है। एक अ धक समावेशी एकजुट और उत्पादक राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से हाल ही में अनावरण की गई राष्ट्रीय शक्षा नीति 2020 में मानव मंत्रालय द्वारा एक महत्वपूर्ण सुधार आया है। संसाधन वकास एमएचआरडी। नीति की मंशा कई मायनों में आदर्श प्रतीत होती है ले कन यह कार्यान्वयन है जहां सफलता की कुंजी है। एनईपी 2020 के तहत, सुधारों के फोकस क्षेत्र छात्रों के बीच 21 वीं सदी के कौशल को वक सत करना चाहते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण सोच समस्या समाधान रचनात्मकता और डजिटल साक्षरता शा मल है। तकनीकी प्रगति के रूप में तेजी से वैश्वीकरण और अभूतपूर्व वकास जैसे क को वड -19 महामारी - काम के भ वष्य को बदल देते हैं, मौजूदा शक्षा मॉडल को वैश्विक अर्थव्यवस्था की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है।

<u>सन्दर्भ:</u>

1.https://www.researchgate.net/publication/343769198_Analysis_of_the_Indian_National_Educatio n_Policy_2020_towards_Achieving_its_Objectives

2.https://www.researchgate.net/publication/346654722_Impact_of_New_Education_Policy_2020_o n_Higher_Education

3. https://www.education.gov.in › ...पीडीएफ राष्ट्रीय शक्षा नीति 2020 - शक्षा मंत्रालय भारत सरकार

4.https://www.google.com/amp/s/www.hindustantimes.com/education/new-education-policy-2020- हाइलाइट्स-की-टेकअवे-ऑफ-नेप-टू-मेक-इं डया-ए- वैश्विक-ज्ञान-महाशक्ति/.html

5.https://niepid.nic.in › nep_2020PDF, राष्ट्रीय शक्षा नीति 2020 - NIEPID

6.https://assets.kpmg › 2020/08PDF:राष्ट्रीय शक्षा नीति 2020 का प्रभाव और उच्च शक्षा के अवसर।kpmg

7.https://www.ugc.ac.in › 5294...पीडीएफ एनईपी 2020 की मुख्य वशेषताएं: उच्च शक्षा